

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KAILASH SONI (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हुसैन दलवर्झ (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

۔ محترمہ کیکشل پروئی (بہار) : مہودے، میں بھی خود کو اس وشنے سے سمبندھ کرنے ہوں۔

MR. CHAIRMAN: Please send your name by slips. मेरा एक सुझाव है कि यह वृद्धाश्रम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Elders' home, not old age home. ऐसी कोई अच्छी शब्दावली हिन्दी में भी हो सकती है, वरिष्ठ नागरिक आश्रम, ऐसा हो सकता है, because हम भी वरिष्ठ नागरिक हैं, हम भी कल वृद्ध हो सकते हैं।

SHRI DEREK O'BRIEN: Elder's home.

श्री सभापति: वह तो English में है। Elder's home. हिन्दी के लिए इन्होंने कहा। यह just observation है। अभी तक जो चल रहा है, वह तो है ही।

Shortage of infrastructure for police training

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, आज मैं प्रदेशों में पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग व उससे संबंधित इंफास्ट्रक्चर की कमी को लेकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वे पूरी क्षमता के साथ, पूरी मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आज देश में पुलिस टू पर्सन रेश्यो बहुत असंतोषजनक

†Transliteration in Urdu script.

[श्री संजय सेठ]

है। जहाँ संयुक्त राष्ट्र ने 450 आदमियों पर एक पुलिसकर्मी रखा है, वहाँ इंडिया के अंदर 1000 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। हर जगह पर, हर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की बहुत कमी है। आज पुलिसकर्मियों पर जितना बोझ है, उसका प्रभाव उनकी दिनचर्या पर भी दिखाई देता है। वे जितनी मेहनत करते हैं, शायद उतनी किसी और डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता होगा। उनके ऊपर इतना मानसिक तनाव रहता है, उसको देखते हुए आज नियुक्तियों की जरूरत है। हर प्रदेश के अंदर जो नियुक्तियों की कमियाँ हैं, उनको पूरा करने की जरूरत है। पूरे देश में करीब साढ़े पाँच लाख पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं। अगर उत्तर प्रदेश को देखें, तो करीब सवा लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्तियाँ होनी हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी आ रही है, वह यह है कि उनकी ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सर, उत्तर प्रदेश में एक साल में केवल 6,800 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग पा सकते हैं, तो सर, अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो इन सवा लाख पुलिसकर्मियों को भर्ती मिलने में 15 साल लगेंगे। सर, अगर इतनी कमी रहेगी, तो कैसे पुलिसकर्मी भर्ती होंगे, कैसे उनकी पुलिस की ट्रेनिंग होगी? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से कहूँगा, क्योंकि वे पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ से आर्थिक व्यवस्था करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि वे केन्द्र से प्रदेशों के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था करें, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो सके और उससे उनकी नियुक्तियाँ हो सके।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**Need to prepare a scheme for irrigation of unirrigated areas of
Champanar District of Bihar**

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): सर, मैं सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पूर्वी चम्पारण जिले के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है एवं वे उस पर आधारित गतिविधियों पर निर्भर हैं। यह जिला, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं बागमती नदियों के मैदानी क्षेत्रों में स्थिति है तथा जिले का क्षेत्रफल 3,968 वर्ग किलोमीटर अर्थात् 1,532 वर्ग मील है। कृषि हेतु 3,03,923 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इसमें सिंचित क्षेत्र 1,76,115 हेक्टेयर है, जबकि असिंचित क्षेत्र 1,27,808 हेक्टेयर है। जिले में सामान्य वर्षा साधारणतः 1,241.6 मिली मीटर वर्षा होती है। जिले की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। वर्षा ऋतु में बागमती नदी की बाढ़ एवं गर्मी में सूखे के कारण यहाँ हर साल कई उत्तार-चढ़ाव देखे जाते हैं, जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है। गन्ना किसानों के सामने भी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। चीनी मिलों के लगातार बंद होने के कारण उन्हें अपनी फसल दूर-दराज के क्षेत्रों में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण आर्थिक नुकसान होता है। जिले का लगभग 42 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र असिंचित होने से लोगों का आर्थिक, सामाजिक परिवेश बहुत अधिक प्रभावित